# उत्तर प्रदेश

# विशिष्ट करेंट अफेयर्स

# अक्टूबर 2022

## स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 : गाज़ियाबाद को मिला प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान

• 1 अक्टूबर, 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाज़ियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान प्राप्त किया है।

• यह गाज़ियाबाद की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पर और देश में 18वें नंबर पर रहा था। 16 लाख से अधिक आबादी वाले गाज़ियाबाद को थ्री स्टार रेटिंग मिली है और ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।

• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाज़ियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर का नंबर है।

• देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सिर्फ गाज़ियाबाद और मेरठ शामिल हैं। गाज़ियाबाद 12वें और मेरठ 15वें नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर इंदौर रहा।

• इसी तरह एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा देश में पाँचवे और प्रदेश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोज़ाबाद चौथे और गोंडा पाँचवे स्थान पर है। एक लाख से 10 लाख की कैटगरी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा के अलावा कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है।

• ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बिगड़ी है। 2021 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान छठा था, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का स्थान 10वाँ आया है।

• एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला, वहीं एक लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला।

• बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है।

## आईजीआरएस थानों की रैंकिंग में वाराणसी कमिश्नरेट के तीन थाने उत्तर प्रदेश में नंबर वन

• 7 अक्टूबर, 2022 को वाराणसी के पुलिस आयक्त ए. सतीश गणेश ने बताया कि आईजीआरएस थानों की रैंकिंग में कमिश्नरेट वाराणसी के तीन थाने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहले स्थान पर आए हैं।

• पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश के अनुसार आईजीआरएस निस्तारण रैंकिंग में कमिश्नरेट वाराणसी के सिगरा, आदमपुर और दशाश्वमेध थाने को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इन तीनों थाने के प्रभारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

• पुलिस आयुक्त ने कहा कि आईजीआरएस की रैंकिंग में एकदम निचले पायदान पर आने वाले तीन थानों – कोतवाली, चितईपुर और पर्यटक की खराब रैंकिंग के कारणों की समीक्षा डीसीपी स्तर के अधिकारी से कराई जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारियों पर कार्यवाही भी तय है। तीनों प्रभारियों को चेतावनी नोटिस जारी की गई है।

• उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जन-सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में वाराणसी के थाने प्रदेश भर में अव्वल हैं।

• जन-सुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल संबंधित थानों के लिये ऑनलाइन प्रेषित करती है। थाना प्रभारी प्राप्त संदर्भों की जाँच ऑनलाइन दिये गए समय के अनुसार संबंधित को प्रेषित करते हैं। जन-सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का आईजीआरएस सेल के अधिकारी और कर्मचारी समाधान करते हैं।

## केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 8 नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी

• 7 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा परियोजना के लिये राष्ट्रीय मिशन के तहत राज्य में सीवरेज प्रबंधन सहित आठ नई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।

• प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक में सीवेज प्रबंधन के लिये चार परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें एक वाराणसी में भी है।

• इस परियोजना में अस्सी नल्ला (Assi Nullah) के दोहन के लिये 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 09 करोड़ रुपए है।

• सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वाराणसी की परियोजना का लक्ष्य तीन नालों – अस्सी, सामने घाट और नखी से शून्य अनुपचारित निर्वहन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

• अन्य परियोजनाओं में 13 एमएलडी एसटीपी का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण शामिल हैं। मथुरा-वृंदावन की इन परियोजनाओं में यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 11 नालों को अवरुद्ध और मोड़ने की परिकल्पना की गई है। वृंदावन और मथुरा के कोसी कलां में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा।

• चार ज़िलों- हापुड़, बुलंदशहर, बदायूँ और मिर्ज़ापुर में जैव-विविधता पार्क स्थापित करने की एक बड़ी परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई है। इनके नाम हैं मिर्ज़ापुर में मोहनपुर बायोडायवर्सिटी पार्क, बुलंदशहर में रामघाट बायोडायवर्सिटी पार्क, हापुड़ में आलमगीरपुर बायोडायवर्सिटी पार्क और बदायूँ में उझानी बायोडायवर्सिटी पार्क।

## उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड में एक-एक बागवानी मॉडल गाँव होंगे विकसित

• 7 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने लखनऊ के उद्यान भवन में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक बागवानी विकास के कार्यक्रमों को पहुँचाने के मकसद से प्रत्येक विकासखंड में एक-एक बागवानी मॉडल गाँव विकसित करने का निर्देश दिया।

• उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक मॉडल गाँव का उपनिदेशक और डीएचओ स्तर के अधिकारी निरीक्षण करेंगे। साथ ही, जानकारी के लिये मॉडल गाँव के बाहर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जाएंगे। इस बोर्ड में दर्शाया जाएगा कि संबंधित गाँव को मॉडल विलेज के रूप में चिह्नित किया गया है।

• उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग की रिक्त उपजाऊ भूमि पर आलू, बीज उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये विभागीय फार्म हाउस व उत्पादन इकाइयों के पूर्ण विवरण के साथ परिसंपत्तियों के लिये पंजिका अनुरक्षित की जाए तथा उद्यान विभाग की ऐसी भूमि और भवन, जो राजस्व के अभिलेखों में अंकित नहीं हैं, उसे अंकित कराने का कार्य किया जाए।

• उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नवोन्मेषी कार्यक्रमों के तहत ड्रैगन फ्रूट, स्ट्राबेरी आदि फसलों का क्षेत्र विस्तार करते हुए गुणात्मक उत्पादन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाए। किसानों को मंडी के पास कोल्ड रूम बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

• उन्होंने निर्देश दिये कि 'पर ड्राप-मोर-क्रॉप'के तहत कम प्रगति वाले ज़िलों को सप्ताहवार लक्ष्य देकर समीक्षा की जाए। 20 अक्टूबर तक रबी की फसल के बीज वितरित कर दिये जाएँ।

• कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करते हुए बागवानी विकास के सभी आयामों को समेकित एवं क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाए। सभी उपनिदेशक और उद्यान अधिकारी अपने ज़िले में होने वाली औद्यानिक फसलें कितनी मात्रा में हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएँ।

• समीक्षा बैठक में मधुमक्खी पालन के विकास के लिये एक विशिष्ट सेंटर आफ एक्सीलेन्स, लखनऊ में एवं संरक्षित खेती के तहत लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, हापुड़ को चिह्नित कर पाली हाउस/शेडनेट हाउस की स्थापना कराने का निर्णय लिया गया।

## लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिये बनीं ब्रिटेन की उच्चायुक्त

• 10 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव 'एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण'में भारत में एक दिन के लिये ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बनीं।

• ब्रिटिश दूतावास ने बताया कि जागृति यादव एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण की छठवीं विजेता हैं।

• जागृति यादव ने एक दिन के लिये उच्चायुक्त प्रतियोगिता का छठा संस्करण जीतने के बाद भारत में ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिक के रूप में एक दिन बिताया। जागृति ने राजनयिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी अनुभव किया, जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक की। इस दौरान जागृति कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुईं।

• विदित है कि वर्ष 2017 से सालाना इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं को अगली पीढ़ी के लिये सशक्त बनाना है।

• भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर अजय कुमार सूद के साथ, जागृति ने स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करने वाली एक पुस्तक भी लॉन्च की।

## मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड

• 12 अक्टूबर, 2022 को मीडिया समूह द्वारा आयोजित 'इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड' समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

• इस समारोह में अवार्डों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति श्रेणी में उनके शानदार काम के लिये यह सम्मान मिला है। हालाँकि इस अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौज़ूद नहीं हो सके थे। उन्होंने इस अवार्ड को राज्य की 25 करोड़ जनता को समर्पित किया।

• मीडिया समूह द्वारा आयोजित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में मनोरंजन, राजनीति, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में प्रेरणास्पद कार्य करने वाली भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया गया है।

• इस श्रेणी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सहित कई बड़े नाम शामिल थे।

## धान खरीद नीति और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन

• 13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 'धान खरीद नीति' की घोषणा सहित कृषि क्षेत्र के लिये कई तरह की छूट और राज्य में 'उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड' के गठन का फैसला लिया गया।

• कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2,060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

• कृषि मंत्री ने बताया कि हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झाँसी ज़िलों में धान खरीदी की अवधि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक है और रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तथा प्रयागराज के लिये यह अवधि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक है।

• उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और किसानों से सभी खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनों के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान की खरीद की जाएगी।

• धान की खरीद खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, मंडी परिषद, यूपीएस और भारतीय खाद्य निगम जैसी छह एजेंसियों के 4,000 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।

• धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान की कीमत का भुगतान किया जाएगा।

## उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी नई कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी

• 13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को कपड़ा हब बनाने हेतु इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने और सभी इकाइयों का विकास सुनिश्चित करने के लिये एक नई कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी दी गई।

• मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 को मंज़ूरी दी है तथा इसमें किसी भी तरह का संशोधन करने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

• नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों, जैसे- हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत् विकास करना है।

• नीति का विशिष्ट उद्देश्य कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित करना, पाँच लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करना, निजी क्षेत्र में पाँच कपड़ा और परिधान पार्क विकसित करना तथा हथकरघा और पावरलूम बुनकर की आय में वृद्धि करना है।

• संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कपड़ा एवं परिधान नीति-2022 में कपड़ा क्षेत्र में निवेश करने वाली इकाइयों को निवेश आकर्षित कर रोज़गार पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में वित्तीय सुविधाओं के साथ विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान था।

• यह नीति प्रख्यापन की तारीख से पाँच साल के लिये प्रभावी होगी। इस नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा और तीन लाख रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

## लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में कूड़े से बनेगी सीएनजी

• 17 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इंदौर की तर्ज़ पर प्रदेश के तीन शहरों- लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में कूड़े से सीएनजी निर्माण के प्लांट लगाए जाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

• विदित है कि इंदौर की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश के भी 4 शहरों में गीले कचरे से सीएनजी बनाने की तैयारी है। कूड़े से सीएनजी बनाए जाने की मंज़ूरी के बाद लखनऊ, गाज़ियाबाद, प्रयागराज में पीपीपी मॉडल पर सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि गोरखपुर भी कतार में है।

• इनमें रोज़ाना 34000 किलो सीएनजी बनेगी तथा इसे बनाने में रोज़ाना करीब 1000 टन कचरा इस्तेमाल होगा। इससे 3.65 लाख मीट्रिक टन कचरा कूड़ा निस्तारण प्लांट में जाने से बचेगा।

• लखनऊ और गाज़ियाबाद में एक ही कंपनी एवर इनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कूड़े से सीएनजी बनाएगी, जबकि प्रयागराज में इंडो इनवायरो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी को ज़िम्मेदारी दी गई है। इन कंपनियों को खुद अपने खर्चे पर प्लांट लगाना होगा। नगर निगम की तरफ से इन्हें कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी।

• लखनऊ तथा गाज़ियाबाद नगर निगम कंपनी को एक रुपए की लीज़ पर 12-12 एकड़ ज़मीन देंगे, जबकि प्रयागराज और गोरखपुर नगर निगम को 10-10 एकड़ ज़मीन देना होगा। इस ज़मीन के बदले नगर निगम को रॉयल्टी भी मिलेगी। सीएनजी बनाने वाली कंपनी लखनऊ और गाज़ियाबाद को प्रतिवर्ष 74-74 लाख तथा प्रयागराज और गोरखपुर नगर निगम को 56-56 लाख रुपए रॉयल्टी देगी।

• कूड़े से सीएनजी बनाने का प्लांट लगने के बाद इन चारों शहरों में रोज़ाना 2.50 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीनहाउस गैसेज़ कम होंगी।

• लखनऊ तथा गाज़ियाबाद के लिये सीएनजी बनाने में 300-300 टन गीले कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि प्रयागराज और गोरखपुर के प्लांट में 200-200 टन कचरा रोज़ाना इस्तेमाल होगा। इस तरह चारों शहरों में रोज़ाना 1000 टन कचरे से 34000 किलो सीएनजी बनेगी।

## उत्तर प्रदेश ने कपड़ा और परिधान नीति की घोषणा की

• हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने और उत्तर प्रदेश को कपड़ा एवं परिधान उद्योग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कपड़ा और परिधान नीति की घोषणा की।

• गौरतलब है कि 13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश कपड़ा और परिधान नीति को मंज़ूरी दी गई थी।

• नीति की घोषणा करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह नीति रोज़गार प्रधान है और इसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को आकर्षित करना तथा 5 लाख से अधिक नई नौकरियाँ पैदा करना है।

• नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर के परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों, जैसे- हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान का सतत् विकास करना है।

• मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कपड़ा और वस्त्र नीति सभी हितधारकों से परामर्श करने और उनकी चिंताओं का ध्यान रखने के बाद तैयार की गई है। नीति को निवेशक अनुकूल बनाने के लिये कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है और निवेशकों की सुविधा के लिये एक हेल्प डेस्क बनाई गई है।

## अब उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी हिन्दी में

• 19 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक श्रुति सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की तर्ज़ पर अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिये हिन्दी भाषा की पाठ्य-पुस्तक पेश करने हेतु सरकार ने एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

• महानिदेशक श्रुति सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जिस तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है, वह तीन विषयों पर एमबीबीएस हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा कर रहा है। इनमें जैव रसायन, शरीर रचना और चिकित्सा शरीर विज्ञान शामिल हैं।

• इसके अलावा अन्य एमबीबीएस पाठ्य-पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है और तीन सदस्यीय पैनल समिति इस अनुवाद की जाँच करेगी।

• गौरतलब है कि हाल ही में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिन्दी में शुरू की गई है।

• चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि लगभग एक महीने पहले समिति का गठन किया गया था और मेरठ स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से इन पुस्तकों को पहले अपनाने की उम्मीद है। अभी हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकें केवल एमबीबीएस छात्रों तक ही सीमित रहेंगी।

• उन्होंने कहा कि इस कदम से छात्रों, विशेष रूप से हिन्दी-माध्यम पृष्ठभूमि वाले छात्रों को अपनी भाषा में अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को आसानी से समझने में मदद मिलेगी।

• चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक एनसी प्रजापति ने कहा कि पैनल चिकित्सा शब्दावली का अनुवाद और पाठ्य-पुस्तकें हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। संपूर्ण पाठ का अनुवाद करना संभव नहीं है, क्योंकि यह छात्रों के लिये जटिल साबित होगा।

## उत्तर मध्य रेलवे हुआ शत-प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का पाँचवा ज़ोन

• हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) शत-प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का पाँचवा ज़ोन बन गया है। यहाँ के सभी ब्रॉड गेज रेलमार्ग का अब पूर्णरूप से विद्युतीकरण हो गया है।

• वर्तमान में देश के 18 ज़ोनल रेलवे में अभी चार ज़ोन पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे ही ऐसे ज़ोन थे, जो पूर्णरूप से विद्युतीकृत थे। अब इसमें उत्तर मध्य रेलवे भी शामिल हो गया है।

• इस रेलखंड में खजुराहो से ललितपुर के बीच ईशानगर-उदयपुर के बीच 76 किमी. विद्युतीकरण का कार्य बीते वित्तीय वर्ष में रह गया था, जिसे केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (कोर) द्वारा 20 अक्टूबर को पूरा कर लिया गया है। अब यह रूट इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों के संचालन के लिये तैयार हो गया है।

• अब इस रेलखंड का विद्युतीकरण होने के साथ ही एनसीआर के ब्रॉड गेज वाले सभी रेलमार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। इसका लाभ यह होगा कि अब महोबा-खजुराहो-उदयपुरा होते हुए ललितपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही, महोबा से छतरपुर होते हुए ललितपुर तक मेमू ट्रेनें चल सकेंगी।

• ईशानगर-उदयपुरा रेलखंड के विद्युतीकरण के साथ ही उत्तर मध्य रेलवे ज़ोन में 3222 रूट किमी. ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण हो गया है। इस नए रूट पर 110 किमी. प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकेंगी, यानी प्रयागराज से महोबा होते हुए ललितपुर तक 110 किमी/घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकेगी। इससे यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

• गौरतलब है कि उत्तर मध्य रेलवे अपने वर्तमान स्वरूप में 1 अप्रैल, 2003 को अस्तित्व में आया था। उत्तर मध्य रेलवे भारत के विस्तृत क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय प्रयागराज (इलाहाबाद) में है और इसमें तीन मंडल- प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा शामिल हैं।

## तराई हाथी अभयारण्य को केंद्र की मंज़ूरी

• 23 अक्तूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिज़र्व (टीईआर) को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिज़र्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत ज़िलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिज़र्व सहित 3,049 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

• उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार, विभाग ने अप्रैल में प्रस्ताव तैयार किया था और इसे 11 अक्तूबर को केंद्र को भेज दिया था। टीईआर के लिये केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंज़ूरी मिलने के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।

• गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिज़र्व के अस्तित्व में आने के साथ, दुधवा टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो चार प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों – बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा।

• दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के अलावा, हाथी रिज़र्व में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर ज़ोन और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के कुछ हिस्से शामिल होंगे।

• तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर होगी, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिये, क्योंकि यह भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जहाँ हाथियों की सीमा-पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या है।

• केंद्र हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो मानव-हाथी संघर्षों को सँभालने में मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभयारण्य की स्थापना से उनके संरक्षण के प्रति हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।

• साथ ही, परियोजना हाथी के तहत प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता का उपयोग दुधवा के शिविर में मौजूद हाथियों के प्रबंधन में किया जाएगा और मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं, जो वर्तमान में राज्य पर निर्भर हैं, को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा।

• उल्लेखनीय है कि दुधवा टाइगर रिज़र्व ने दशकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित किया है, जिसमें बसंता-दुधवा, लालझड़ी (नेपाल) -सथियाना और शुक्लाफांटा (नेपाल)-ढाका-पीलीभीत-दुधवा बफर ज़ोन कॉरिडोर शामिल हैं। प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत तराई एलीफेंट रिज़र्व इन गलियारों को पुनर्जीवित करने या बहाल करने में मदद करेगा, जो खराब हो गए हैं।

## लखनऊ में होगा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन

• 28 अक्टूबर, 2022 को वाराणसी में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में हुई इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में आईआईए की फूड प्रोसेसिंग कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन दीपक बजाज ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 2 से 4 नवंबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन होगा।

• दीपक बजाज ने बताया कि इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन तीनदिवसीय होगा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों से 100 से अधिक उद्यमी हिस्सा लेंगे।

• फूड प्रोसेसिंग मशीनों तथा फूड प्रोसेसिंग तकनीकी का यह देश का सबसे बड़ा एक्सपो है और इसमें बनारस समेत आसपास के ज़िलों से होटल उद्यमी, रेस्टोरेंट संचालक, बेकरी उत्पादों के निर्माता भाग लेंगे।

• इंडिया फूड एक्सपो में एमएसएमई के तहत ओडीओपी के विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे तथा देश एवं विदेश के फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मशीनों पर हुए नए इनोवेशन को भी इसमें शामिल किया गया है।

• इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने इंडिया फूड एक्सपो के संबंध में सरकार को उद्योगों में उपयोग होने वाले विभिन्न लाइसेंस जैसे फायर, प्रदूषण आदि की प्रक्रिया को आसान करने तथा टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 की अनुदान राशि अवमुक्त करने को कहा, जिससे उद्योगों का सुगम संचालन हो सके।

## उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिये तैयार

• 30 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (चीनी उद्योग) संजय भूसरेड्डी ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक बनने के लिये तैयार है। राज्य में उद्योग का आकार 12,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है।

• अतिरिक्त मुख्य सचिव (चीनी उद्योग) संजय भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इथेनॉल क्षमता 2 अरब लीटर प्रति वर्ष आँकी गई है, जो पाँच साल पहले 240 मिलियन लीटर प्रति वर्ष से लगभग आठ गुना अधिक है। अगले कुछ वर्षों में राज्य की इथेनॉल क्षमता 25 अरब लीटर प्रति वर्ष तक पहुँचने की उम्मीद है।

• उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र की डिस्टिलरीज ने पिछले पाँच वर्षों में राज्य की समग्र इथेनॉल क्षमता को उन्नत करने के लिये लगभग 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

• राज्य सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और इस क्षेत्र को चीनी बाज़ार की चक्रीय प्रकृति से बचाने के लिये गन्ने की फसल को एक आकर्षक इथेनॉल मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।

• संजय भूसरेड्डी ने कहा कि मौजूदा 2022-23 गन्ना पेराई सत्र में, पाँच निजी मिलें चीनी का उत्पादन किये बिना सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल का निर्माण करेंगी। इसके अलावा, 71 अन्य मिलें बी-हैवी शीरे (B-heavy molasses) से इथेनॉल का उत्पादन करेंगी।

• इस बीच राज्य का गन्ना क्षेत्र 3 प्रतिशत या 84,000 हेक्टेयर बढ़कर 85 मिलियन हेक्टेयर से अधिक होने का अनुमान है, जबकि चालू सीजन में गन्ने का उत्पादन 2.35 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है। वर्तमान गन्ना पेराई सत्र के दौरान कुल 120 चीनी मिलें- 93 निजी इकाइयाँ, 24 सहकारी इकाइयाँ और तीन उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाइयाँ संचालित होंगी।

• विदित है कि 5 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवार उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें चीनी, इथेनॉल, गुड़, बिजली सह उत्पादन, गुड़, खांडसारी (अपरिष्कृत चीनी) आदि इसके उप-उत्पाद पोर्टफोलियो में शामिल हैं। प्रदेश में समेकित वार्षिक गन्ना अर्थव्यवस्था लगभग 50,000 करोड़ रुपए की है।